

ज्ञान तत्व अंक 158

(क) लेख, मंहगाई का भूत ।

(ख) कश्मीर में अमरनाथ यात्रा में विध्न पैदा करने और मुसलमानों द्वारा अपनी बात मनवाने पर प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(ग) संघ के एक प्रमुख श्री एम 0 जी 0 बैद्य द्वारा गांधी के हत्या के संबंध में प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(घ) अपनो से अपनी बात ।

(च) अर्थ शास्त्र और राजनीति शास्त्र पर पंकज आचार्य जी का विचार ।

मंहगाई का भूत

आज पूरे भारत में मंहगाई सबसे बड़ी समस्या के रूप में स्थापित हो चुकी है। छोटे से छोटा आदमी भी मंहगाई से परेशानी अनुभव कर रहा है और बड़ा से बड़ा आदमी भी। पान दुकान में भी मंहगाई पर ही चर्चा केन्द्रित है और हवाई जहाज में भी। मुझे तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं जो मंहगाई से त्रस्त न हों। वैसे तो स्वतंत्रत भारत के साठ वर्षों में हमेशा ही मंहगाई से परेशानी अनुभव की गई किन्तु चुनावों के समय आम आदमी को यह अनुभव और दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही या तो महसूस होने लगता है या महसूस कराने की परंपरा रही है। इस वर्ष भी मंहगाई का एक भूत के रूप में स्थापित होना यह सिद्ध करता है कि अवश्य ही आम चुनाव बहुत नजदीक हैं।

मेरे अपने साथी भी मंहगाई से त्रस्त है। कुछ साथी तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। वे न मंहगाई की परिभाषा करना चाहते हैं न विरुद्ध में कोई बात सुनना चाहते हैं। बस टी.बी.में बढी मंहगाई का सरकारी आकडा सुनते ही उनकी कमर टूटने लगती है और उनका भाषण शुरू हो जाता है। फिर तो वे इस सम्बन्ध में कुछ सुनते ही नहीं। मुझे मंहगाई के सम्बन्ध में चर्चा में सुखद आश्चर्य हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति प्यारे लाल जी खंडेलवाल से अस्पताल में मैं मिलने गया और मंहगाई पर बात छिड़ गयी। उन्होंने स्वयं माना कि यह एक राजनैतिक हथकण्डा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में और विस्तृत विवेचना की। चुनाव वर्ष में मंहगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर संतुलित विवेचना से मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव ही उत्पन्न हुआ अन्यथा कांग्रेसी कार्यकर्ता तक स्वीकार करता है कि वह मंहगाई से परेशान है।

प्रश्न उठता है कि मंहगाई की परिभाषा क्या है? मुद्रा स्फीति और मंहगाई में फर्क क्या है? मैंने पूर्व में भी बहुत गहन विचार किया था और अब पुनः गंभीरता से सोचा तो पाया कि मंहगाई एक अस्तित्व हीन शब्द है जिसका कभी कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं होता। वास्तविक शब्द तो है मुद्रा स्फीति जिसका अर्थ होता है नगद रूपया पर अघोशित कर और प्रभाव सिर्फ उसी पर होता है जिसके पास नगद रूपया हो कल्पना करिये कि किसी व्यक्ति को अपने एक दिन का वेतन सौ रूपया मिलता है और उसे सौ रूपये में दस किलो औसत वस्तुएँ प्राप्त होती रहती हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी मजदूरी तो एक सौ दस रूपया हो गई और मुद्रा स्फीति बढ़ने के कारण

कुल वस्तुएँ दस किलो ही मिली तो उसे महंगाई महसूस होने लगती है और उसकी कमर टूटने लगती है जब कि वेतन वृद्धि और मूल्य वृद्धि किसी महंगाई के परिणाम न हो कर मुद्रा स्फीति के परिणाम हैं और मुद्रा स्फीति का तब तक कोई प्रभाव नहीं होता जब तक मुल्यों के अनुपात में उसका वेतन बढ़ता रहे। इस तरह महंगाई न कभी आई है न आयेगी क्यों कि वेतन वृद्धि के अनुपात में मूल्य वृद्धि हमेशा ही कम रही है। स्वतंत्रता के बाद यदि आज तक का आकलन करे भी तो मुद्रा स्फीति करीब सत्तर गुनी बढ़ी है जब कि मजदूरी डेढ़ सौ गुनी और कर्मचारियों का वेतन तीन सौ गुना करीब बढ़ा है। इसके बदले में सोना चाँदी जमीन अधिक बढ़ा है

ए दालें खाद्यतेल कृत्रिम ऊर्जा आदि स्थिर हैं। अनाज कपडा आदि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ती हुई है और टेलीफोन, रेडियो, घडी आदि तो कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। सोचने की बात है कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी कौन सी वस्तुएँ महंगी हुईं जिनसे आम लोगों कि कमर टुट गई। खाद्य पदार्थ और कपडा तो सस्ता हुआ है और सोना चाँदी जमीन महंगी होने से किसी आम की कमर टूटती नहीं। फिर इतना हल्ला क्यों? हल्ला इस लिए नहीं होता है कि महंगाई से जनजीवन पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। हल्ला तो इस बात का होता है कि व्यक्ति को आज जो सुविधा प्राप्त थी उसमें कोई कटौती हो रही है। यदि दस वर्ष पहले फोन का चार्ज दस रूपये था और आज एक रूपया है तो ठीक है। यदि कल दो रूपया हो जाय तो फोन भी महंगा घोषित हो जायगा और महंगाई में शामिल हो जायगा। मैं तो साठ वर्ष पूर्व भी महंगाई का ऐसा ही प्रचार और हल्ला सुनता था और आज भी वैसा ही है मुझे तो हल्ले में कभी फर्क नहीं दिखा।

फिर भी इस बार की महंगाई का कुछ अलग प्रभाव है। इस बार ऐसी वस्तुएँ महंगी हुई हैं जो आम आदमी के उपयोग की हैं जैसे अनाज, दाल ,खाद्यतेल आदि किसी वस्तु के महंगा होने के चार कारण हो सकते हैं।

1 मुद्रास्फीति बढ़े 2 वस्तु का उत्पादन कम हो 3 वस्तु का निर्यात अधिक हो 4 वस्तु का उपयोग अधिक होने लगे। मुद्रा स्फीति का प्रभाव होता नहीं क्यों कि आम तौर पर मुद्रा स्फीति की तुलना में वेतन भी अधिक बढ़ता रहा है और श्रम मूल्य भी। जो लोग कहते हैं कि आज वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं और और वेतन छ माह बाद बढ़ेगा तब तक तो उस आदमी का कचूमर ही निकल जायगा वे बिल्कुल झूठ बोलते हैं

क्योंकि यह कैसे माना गया कि वेतन पहले बढ़ा कि मूल्य। यदि मैं कहूँ कि छ माह पूर्व वेतन बढ़ा और आज मूल्य तो इस में गलत क्या है।

अन्डा पहले कि मुर्गी यह विवाद न कभी सुलझा है न कभी सुलझेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत की कुल विकास दर नौ प्रतिशत है जो सम्पन्नों की सत्रह प्रतिशत और बिल्कुल गरीबों की एक प्रतिशत करीब है। यदि मुद्रा स्फीति के प्रभाव से गरीब आदमी को आज ग्यारह प्रतिशत सामान कम मिल रहा है तो विकास दर का उस व्यक्ति पर कितना प्रभाव पडता है? अर्थात वह गरीब आदमी ग्यारह प्रतिशत महंगाई के बाद भी विकास कर रहा है या उसका जीवन स्तर ग्यारह में एक घटकर दस प्रतिशत नीचे जा रहा है

यदि हम वस्तु के उत्पादन की कमी की बात करें तो जिन वस्तुओं की भारी मूल्य वृद्धि हुई

है उनके उत्पादन में कोई विशेष कमी नहीं आई है। यदि हम माँग वृद्धि और क्रय शक्ति की वृद्धि की सोचें तो गेहूँ चावल दाल खाद्यतेल का माँग वृद्धि या क्रय शक्ति बढ़ने से कोई सम्बन्ध नहीं। सीमेंट और लोहा का इससे आंशिक संबंध है। यदि हम आयात निर्यात पर गंभीरता से विचार करें तो महंगाई का सारा खेल इसी पर निर्भर है। सरकार कठपुतली के समान आयात निर्यात को नचाती रहती है जिसका प्रभाव मुल्यों पर पड़ता है। सरकार साम्यवादियों को नाराज नहीं करना चाहती और साम्यवादी खाड़ी देशों के हितों की भारत में लम्बे समय से देखभाल करते रहते हैं। भारत में डीजल पेट्रोल के मूल्य न बढ़ें, इन सब की खपत कम न हो, इन सबका आयात भी कम न हो इसकी सर्वाधिक चिन्ता ये विचारे वर्षों से पूरी इमानदारी से करते रहे हैं। इस कार्य के लिए तो ये लोग सरकार तक को कुर्बान करने के लिये तैयार रहते हैं और आप रोज रोज का विवाद सुन भी रहें होंगे कि बिजली की उपलब्धता बढ़ने से होने वाले डीजल पेट्रोल के दुःप्रभाव के लिए बेचारे कितना संघर्ष कर रहे हैं। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं है। अब आप विचार करिये कि यदि डीजल पेट्रोल की खपत कम नहीं करनी है तो आयात करना ही होगा और उसी मुताबिक दुगने चौगुने मुँह माँगे दाम भी उन्हें चुकाने होंगे और उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्यात भी करना होगा भले ही भारत जनता पर उसका कुछ भी और कितना भी प्रभाव क्यों न पड़ता हो। यही और सिर्फ यही एक मात्र कारण है जिसके कारण इस बार कुछ आवश्यक वस्तुओं के दाम इस तरह बढ़े हैं। साम्यवादी इस सहायता के

लिए खाड़ी देशों से धन लेते हैं या नहीं यह बात तो नहीं मालूम किन्तु दोष अन्य दलों को इस तेल के खेल से धन मिलना अब कोई छिपी बात नहीं। इस तरह धन के मामले में तो सबकी सहानुभूति खाड़ी देशों के साथ रहती ही है और बदनाम विचारे अकेले वामपंथी रहते हैं क्यों कि खाड़ी देशों को अमेरिका के विरुद्ध खड़ा रखना भी तो आसान काम नहीं है।

मेरे विश्लेषण अनुसार महंगाई का कोई अस्तित्व न होते हुए भी कांग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं कर पा रही क्यों कि उसने ही तो सिर्फ प्याज और टमाटर की महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव जीत लिया था। अब यदि यह मुद्दा उसके विरुद्ध जा रहा है तो वह किस मुँह से वास्तविक तर्क समाज के समक्ष रखे और कौन उस बात को सुनेगा? कुछ आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का दोष भी कांग्रेस आयात निर्यात की अपनी नीति को नहीं दे सकती क्योंकि उसे भी चुनाव लड़ना है और यह आयात निर्यात ही तो उसके लिए जर्सी गाय का काम करती है।

सरकारी कर्मचारी यह पोल खोलने को तैयार नहीं क्योंकि महंगाई का प्रचार उन्हें कई गुना अधिक वेतन बढ़वाने में सहायक होता है। अन्य अनेक पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता इस असत्य को ही सत्य मान बैठे हैं। उन्हें न महंगाई का पता है न तेल के खेल से कुछ लेना देना है। जो हल्ला समाज में उठ रहा है उसके साथ अपने को जोड़ लेना उनकी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ कि महंगाई के मूद्दे पर समाज में व्यापक विचार मंथन हो और सच समाज के समक्ष प्रकट हो।

कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न(ख) –कश्मीर में अमरनाथ यात्रा में विघ्न पैदा किया गया। वहाँ के मुसलमानों ने संगठित स्वरूप में अपनी बात मनवा ली। आपके विचार में क्या उनका कार्य उचित है?

उत्तर— इस्लामिक संस्कृति यह अच्छी तरह समझती है कि वह अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी हिन्दू और इसाई से अधिक संगठित है भी तथा उस शक्ति का अधिकतम उपयोग करना जानती भी है। इस्लाम ने अब तक अपनी इस शक्ति

का अधिकतम लाभ उठाया भी है। दुनिया का हर मुसलमान बचपन से ही अच्छी तरह पारंगत हो जाता है कि उसे किन परिस्थितियों से झुकना है कब ब्लैक मेल करना है और कब दबाना है। इस निर्णय के लिये उसे उपर के निर्देशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह अपनी प्राथमिकता स्वयं समझता है।

संघ परिवार ने इस्लामिक खतरे को समझा और इस्लामिक तरीके से ही हिन्दुओं को संगठित करना चाहा किन्तु असफल हुआ। हिन्दू इस्लामिक तरीके से संगठित होने के लिए एक मत नहीं हुआ किन्तु इस्लामिक आतंकवाद को हव्वा बना कर अमेरिका ने इस्लाम के विरुद्ध विश्व जनमत जागृति करने में सफलता पाई। सारी दुनियाँ में मुसलमान संदेह के घेरे में आये। मैं स्वयं भी ऐसे लोगों में शामिल हूँ। सारे तर्क वितर्क करने के बाद भी मेरे संस्कार इस्लाम के विरुद्ध कुछ झुक ही जाते हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह झुकाव मेरा दोष है या मुसलमानों का व्यवहार किन्तु यथार्थ तो यह है ही। बहुत सोच विचार के बाद भी मेरा यह निष्कर्ष नहीं बदल रहा कि मुसलमान इस्लाम धर्म को ही मानवता मानता है और हिन्दुत्व मानवता को ही धर्म। इसाइयत की सोच भी हिन्दुत्व से अधिक मेल खाती है और इस्लाम से कम।

भारत के मुसलमानों ने परिस्थितियों को समझकर आतंकवाद के मामले में कदम पीछे खींचने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन रखने शुरू किये। देश भर के मुसलमानों को भाईचारा और आतंकवाद विरोधी वातावरण बनाने के संदेश दिये जाने लगे। कश्मीर के मुसलमानों ने यह नहीं समझा कि यह संदेश उनके लिए भी है। उन्होंने समझा कि यह भाईचारा संदेश सिर्फ वही के लिए है जहाँ मुसलमान कमजोर है। चूँकि वह कश्मीर में मजबूत स्थिति में है इस लिए वहाँ कैसा भाईचारा और कैसा आतंकवाद विरोध। उन्होंने तय किया कि हम किसी तरह अपनी संगठित ताकत को कमजोर नहीं दिखने देंगे। शेष भारत के मुसलमान बेचारे दुविधा में है कि वे क्या स्टैन्ड लें।

कश्मीर में हिन्दुओं की अमरनाथ यात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही है। आतंकवादियों ने इस यात्रा में विघ्न डालने के बहुत प्रयास किये किन्तु सफल नहीं हुए। यह यात्रा दो माह के लिए होती है। कश्मीर सरकार ने बढ़ती भीड़ की असुविधा को देखते हुए

दो माह के लिए यात्रियों को चालीस हेक्टेयर वन भूमि के अस्थाई उपयोग की साईन बोर्ड को छूट दे दी। बस इतनी सी छूट के विरुद्ध विवाद फैल गया। प्रदर्शन हुए। अमर नाथ यात्रियों पर भी आक्रमण हुए। सरकार को झुकाया गया। आदेश रद्द हुआ।

कश्मीर में मुसलमानों ने संगठन शक्ति के बल पर अपनी बात मनवाकर जीत

हासिल कर ली किन्तु प्रश्न कश्मीर में जीत तक सीमित नहीं है। प्रश्न यह है कि शेष भारत के हिन्दुओं के मन में इसका क्या संदेश जायेगा? धारा 370 को अनावश्यक मानते हुए भी और संघ परिवार के व्यापक दबाव के बावजूद भारत के हिन्दू जनमानस ने धैर्य का परिचय देते हुए उससे छेड़छाड़ नहीं की। क्या बाहर के मुसलमानों यह प्रयत्न इस धैर्य पर बहस नहीं छेड़ देगा? कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है जिसे भाईचारा से निपटाया जाय इस धैर्य के नाम पर वहाँ के मुसलमान कब तक शेष भारत को ब्लैक मेल करते रहेंगे। मेरे विचार में तो कश्मीरी मुसलमानों का यह प्रयत्न पूरे भारत के साम्प्रदायिक हिन्दुओं को मजबूत करेगा और यह मजबूती अन्ततोगत्वा कश्मीर सहित पूरे भारत के मुशिलम विश्वास के नये प्रयत्नों को कमजोर करेगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि कश्मीर के मुसलमान जीत का जश्न मनाने की अपेक्षा परिस्थितियों की गंभीरता को महसूस करेंगे और अपने व्यवहार से कट्टरवादी हिन्दुओं की इस कहावत को असत्य प्रमाणित कर देंगे कि.....सीधी नहीं होती। कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलामनबी आजाद ने सूझ बूझ का परिचय देते हुए आदेश को रद्द कर दिया और पी डी पी फारूक अब्दुल्ला के साम्प्रदायिक लाभ के प्रयत्न को रोक दिया अन्यथा पी डी पी फारूक अब्दुल्ला आदि के लोग तो लाशों के ढेर की आग पर भी रोटी सेंकने से परहेज नहीं करेंगे।

प्रश्न (ग) ... संघ के एक प्रमुख श्री एम 0 जी 0 बैद्य ने नागपुर में कहा है कि गॉंधी हत्या पूरी तरह गलत कार्य था और हम इस कृत्य की निन्दा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गॉंधी हत्या न राष्ट्र हित में थी न देश हित में। आप उनके इस कथन को किस रूप में देखते हैं?

उत्तर — मैंने पिछले पचास वर्षों से यह माना है कि गॉंधी हत्या एक निन्दनीय कार्य था है और रहेगा। मैं जब भाजपा में था तब भी यह बात स्पष्ट रूप से बोलता भी

था और लिखता भी था। बैद्य जी ने अब जो बात कही है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और भी अच्छा होता यदि इतनी साफ बात संघ के किसी और अधिक वरिष्ठ की ओर से आई होती। सत्य को बिना लाग लपेट के साफ साफ शब्दों में जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाय उतना ही नुकसान कम होता है। संघ ने जो बात अब कहनी शुरू की हैं उसे पहले कहते तो और अच्छा होता किन्तु मेरी यह धारणा है कि कट्टरवादी विचारों के लोग लम्बे समय तक भूल को या तो प्रचार की ताकत पर सही सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं या घुमा फिरा कर उसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं। संघ ने भी वही किया। इन्होंने गॉंधी जी को प्रातःस्मरणीय की सूची में शामिल करके नुकसान की भरपाई चाही थी जो नहीं हुई। क्यों कि गॉंधी हत्या एक पृथक विषय है और प्रातःस्मरणीय में नाम डालना पृथक। बैद्य जी ने जो कुछ कहा है वह चाहे उपर वालों की सलाह से कहा हो या बिना सलाह के किन्तु है एक स्वागत योग्य कदम। संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी यदि यह कदम उठावें तो संघ की बहुत बड़ी सेवा होगी।

बैद्य जी ने चार माह पूर्व एक और ऐसी ही बात कह कर सनसनी फैला दी थी कि कांग्रेस और भाजपा को मिल कर सरकार चलाना राष्ट्रीय समस्याओं का एक अच्छा समाधान है। मैं उनकी इस बात का भी समर्थक बहुत पहले से रहा हूँ। उस समय सोनियाँ गॉंधी ने इस बात से इनकार कर दिया था। अब कुछ हालात बदल गये हैं। अब कांग्रेस

का दूत आडवानी जी से मिला तो उन्होंने उसे खाली हाथ लौटा दिया। इस देश की राजनीति को न देश के हित से मतलब है न समाज हित से। राजनीति तो इन सबका व्यक्तिगत या पारिवारिक व्यवसाय बन गयी है। यह अलग बात है कि बैद्य जी या मैं या ऐसे ही कई और लोग इन पेशेवर लोगों को जनहित राष्ट्रहित की बात कभी कभी कहकर आत्म संतोष कर लेते हैं। यदि बैद्य जी सरीखे कुछ और लोग निकल सके तो हम ऐसे लोगों को ठीक ठीक सुनने समझने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं।

(घ) अपना से अपनी बात

दिल्ली में रहकर आन्दोलन की पृष्ठ भूमि बनाने में तीन वर्षों का समय लग चुका है। आज सबके समर्थन से अच्छा वातावरण बना है। यह वर्ष चुनावी वर्ष होने से

राजनीतिज्ञ सत्ता सघर्ष में आपस में उलझे हुए हैं। ऐसे समय में हमारे लिए आन्दोलन शुरू करने का एक अच्छा अवसर है। माननीय ठाकुर दास बंग ने भी नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया है। अभी सात जुलाई को सेवाग्राम में बंग जी, अमरनाथ भाई गडकरी जी, अविनाश जी, आचार्य पंकज जी तथा मैं बैठकर विस्तृत चर्चा किये। हमारा आन्दोलन का लक्ष्य तो दो सूत्रीय संविधान संशोधन नहीं है किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा के मुद्दे क्या हो यह सोचना था। मेरा सुझाव था कि हम कृषि उपज मंडियों में अनाज दाल खाद्य तेल जैसी स्थानीय उत्पादन की तथा स्थानीय खपत की वस्तुएँ किसानों से सीधा खरीद कर उस मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को बेचें। हम न तो कोई लाईसेंस लेवें न ही सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स दें। इससे किसानों को भी यह पता चलेगा कि कृषि उत्पादनों पर अप्रत्यक्ष कर लगता है तथा उपभोक्ताओं को भी पता चलेगा। यह एक आन्दोलन का रूप ले सकता है। हम माँग करेंगे कि सरकार ऐसा सारा टैक्स लगाने वसूलने या खर्च करने का सारा अधिकार स्थानीय इकाईयों को सौंप दे। बंग जी का सुझाव था कि हमारी सरकारो ने साठ वर्ष से शराब नीति पर अपना एकाधिकार किया हुआ है। वह शराब बन्दी का नाटक भी करती है और शराब बेचती भी रहती है। ग्राम सभा इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले सकती।

हम शराब संबन्धी कानून बनाने के अधिकारों से राज्य सरकार केन्द्र सरकार को मुक्त कर दे और सभी अधिकार स्थानीय इकाईयों तक सीमित कर दें। सरकारे न शराब बन्दी कर सकेगी न बेच सकेगी। यदि कोई कर लगाना हो तो स्थानीय इकाईयों का ही एकमात्र अधिकार होगा। हम इस कानून को लागू कराने के लिए सरकारी कानूनों का उल्लंघन करते हुए शराब बेचेंगे और तब तक बेचेंगे जब तक स्थानीय इकाईयों कानून नहीं बनाती। शराब बेचने का हमारा उद्देश्य शराब को प्रोत्साहन न होकर स्थानीय इकाईयों का सशक्तिकरण मात्र है। अनाज बिक्री के मुद्दे की अपेक्षा शराब का मुद्दा अधिक सशक्त है। कुछ लोग इस मुद्दे पर भ्रम भी फैला सकते हैं जिससे हम प्रभावित न हो ऐसे ही कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं जिससे सरकार का कानून भी टूटता हो तथा उसके आर्थिक श्रोतों पर भी प्रभाव पड़े।

साथ ही यह भी आवश्यक है कि उससे स्थानीय इकाईयों अधिक से अधिक मजबूत हों। हमारा हर प्रयत्न होगा कि राज्य के अधिकार दायित्व तथा हस्तक्षेप घटे।

सभी प्रकार के अच्छे काम सरकार से कराने की माँग करने की गुलाम मानसिकता का भी विरोध करना होगा। जो लोग तम्बाकू रोकने गुटखा बंद करने जैसे जनहित के कार्यों के लिए सरकारी कानून की माँग करते हैं वे या तो नासमझ हैं या सरकारी दलाल। ऐसी आदत को रोकना होगा। इन सब बातों पर विचार करके हम आन्दोलन का मुद्दा भी तय करेंगे तथा रूपरेखा भी बनायेंगे।

हमारा आन्दोलन पूरी तरह अहिंसक होगा हिंसा या बल प्रयोग द्वारा आन्दोलन करने वाले इस बैनर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। हमें यह भी तय करना होगा कि कानून का उल्लंघन और बल प्रयोग के बीच संतुलन और सीमा रेखा क्या हो।

बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि ज्ञानतत्व के अंक 156/57 में सर्वोदय के लिये बहुत तीखी और पीड़ा दायक टिप्पणियाँ की गयी हैं। मैंने यह स्पष्ट किया कि मुझे इस प्रकार की टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए थीं। हमारी पहली प्राथमिकता है आन्दोलन। आन्दोलन से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ रहा है किन्तु अपने ऐसे साथियों को अकारण दुख पहुँचे ऐसी टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। मैंने मित्रों से कहा कि मुझसे भूल हुई है जिसकी सूचना मैं अपने साथियों को भी ज्ञानतत्व के माध्यम से दूँगा। मैंने एक पत्र सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगन बरंट जी को भी लिखा और आश्वासन दिया कि भविष्य में अपने आन्दोलनरत साथियों की भावनाओं का ख्याल रखा जायगा।

इस बैठक में अमरनाथ भाई ने भी खुल कर चर्चा की और आश्वासन दिया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ चर्चा करके सम्मेलन में आने की योजना बनायेंगे। बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि सर्वोदय के कुछ लोग फोन करके सम्मेलन में न जाने का अभियान चला रहे हैं। सोचा गया कि यदि कोई जानबूझ कर ऐसा कर रहा है तो यह उसका विशेषाधिकार है और उसे हम नहीं रोक सकते। यदि कोई भूल से कोई ऐसा कर रहा है तो वह स्वयं समझ जावेगा। हम ऐसी चिन्ताओं को किनारे करके किन्तु पूरी सतर्कता से अपना काम करें। कोई कठिनाई नहीं आयेगी इतना विश्वास रखें।

इस बैठक में यह भी चर्चा हुई की सम्मेलन के महत्व के अनुसार इसे दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन कर देना चाहिए। तदनुसार सम्मेलन की तारिखें एक दिन

के लिए और बढ़ायीं गई अर्थात् 20 एवं 21 को बढ़ाकर 22 तक किया गया। अब सम्मेलन तीन दिनों का होगा।

आप मित्रों से निवेदन है कि आप कम से कम तीन दिनों के लिए इस सम्मेलन में अपने गंभीर मित्रों के साथ आइये। एक दिन पूर्व आ जावें तब और सुविधा होगी। आप को सम्मेलन के प्रातः से ही जुड़ने में सुविधा होगी। साथ ही एक दिन पूर्व होने वाली चर्चाओं में भी हम आपसे अनौपचारिक चर्चा करते रहेंगे। आप इस सम्मेलन की गंभीरता को समझेंगे।

**(च) हमारा अगला कदम
आचार्य पंकज**

व्यवस्था के ठीक ठीक संचालन में समाज शास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। धर्म शास्त्र

अर्थ शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र अपनी अपनी नीतियाँ बनाते समय समाज शास्त्र द्वारा ही मार्गदर्शित भी होते हैं और नियंत्रित भी। समाज शास्त्र ही केन्द्र में होता है। इस सैद्धान्तिक सच्चाई के बावजूद अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र या राजनीतिशास्त्र से जुड़ लोग सामाजशास्त्र पर नियंत्रण का प्रयत्न करते रहते हैं। यह चूहे बिल्ली का खेल चलता ही रहता है। दुनियाँ के अनेक देशों के समाजशास्त्र ने इस संकट को झेला भी है और झेल भी रहे हैं। दुनियाँ का एक भी ऐसा देश नहीं जहाँ के समाजशास्त्र के अन्तर्गत धर्मशास्त्र राजनीति शास्त्र या अर्थ शास्त्र अपनी अपनी नीतियों का निर्धारण करते हों।

लोक तांत्रिक पश्चिमी देशों के अर्थशास्त्र ने समाज व्यवस्था को दबा रखा है तो साम्यवादी देशों के राजनीतिशास्त्र ने या इस्लाम के धर्मशास्त्र ने। भारत एक मात्र ऐसा देश है जहाँ राजनीति अर्थ नीति धर्म नीति तीनों ने समाज व्यवस्था को पूरी तरह घेर रखा है अर्थात् यहाँ समाज शास्त्र की नीति निर्धारण में न कोई भूमिका है न ही नियंत्रण। समाज व्यवस्था इन तीनों के दबाव में घिसटती रहती है।

इन तीनों के बीच भी यदि तुलना करें तो समाज शास्त्र को गुलाम बनाकर रखने में राजनीति की ही भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी है। राजनीति ने धर्म व्यवस्था को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है तथा अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए

पूँजीपतियों से समझौता कर लिया है। इस तरह राजनीति सत्ता और धन को साथ लेकर तथा धर्म को किनारे करके सम्पूर्ण समाज व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करते जा रहीं हैं

इस खतरे को सबसे पहले भारत में महसूस किया गाँधी ने। जिस समय गाँधी ने योजना बनानी शुरू की उस समय कुछ लोग सिर्फ सामाजिक समस्याओं की ही चिन्ता करते थे तो कुछ लोग सिर्फ राजनैतिक समस्याओं तक ही केन्द्रित रहे। अर्थ नीति की चिन्ता तो गुलामी में हो नहीं सकती थी किन्तु समाजशास्त्र या राजनीतिक चर्चाएँ चलती रहती थीं अर्थात् कुछ लोग वेब पंसद दिशा में सक्रिय थे तो कुछ चवसपजपबंस दिशा में गाँधी ने वेब **iopolitical** सामाजिक राजनीति नाम से एक तीसरा ही मार्ग बनाया। वे राजनीति और समाज के सम्बंधों पर गहराई से सोचते भी थे और निष्कर्ष भी निकालते थे। गाँधी जी ने अपने पूरे कार्य काल में भारत की राजनैतिक गुलामी के

विरुद्ध संघर्ष भी किया और भारत की गुलामी समाप्त होने के बाद राजनैतिक सामाजिक सम्बन्धों का एक ब्लू प्रिन्ट भी तैयार करते रहे। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के शीघ्र बाद ही गाँधी जी की हत्या हो गयी। गांधी जी के जीवन काल में उनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति सामाजिक राजनीति (**socoplitical**) की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। गाँधी के बाद भी वह दिशा अधूरी ही रही। सामाजिक या राजनैतिक दिशाओं में अलग अलग काम करने या चिन्तन करने वाले तो मिलते रहे किन्तु एक साथ सोचने समझने वालों का अभाव रहा। लोहिया जी या जयप्रकाश जी ने आशिक रूप से यह प्रयत्न किया भी किन्तु या तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं बनी या कहीं कुछ और अभाव रहा किन्तु सफलता नहीं मिल सकी। पिछले कुछ वर्षों से मैंने बजरंग मुनि जी में **sociopolitical** प्रतिभा का अनुभव किया है। इनकी सामाजिक तथा राजनैतिक दोनों ही प्रकार के विषयों पर स्पष्ट चिन्तन भी है तथा सक्रियता भी। अर्थशास्त्र के मौलिक चिन्तन में भी उनकी सोच सकारात्मक है। इस दिशा में उनकी सोच का लाभ उठाना चाहिए। यह स्पष्ट दिख रहा है

कि राजनीति लगातार समाज व्यवस्था को नियंत्रण में लेती जा रही हैं। अर्थ व्यवस्था तो पूरी तरह उसके नियंत्रण में है ही किन्तु समाज व्यवस्था का भी बहुत थोड़ा सा अंश राजनीति के प्रभाव से बचा है। वोट देने का अधिकार छोड़ कर अन्य सारे अधिकार राजनेताओं

ने अपने पास समेट लिए हैं। वोट देने का अधिकार भी अब किस सीमा तक स्वतंत्र है यह बहस का विषय बना हुआ है अन्यथा धन बल या छल बल से राजनीति इस अधिकार को भी अपने प्रभाव में लेती जा रही है।

ऐसे समय में ,d **sociopolitical** आन्दोलन ही समाज को राजनीति के खूनी पंजे से बचा सकता है। प्रसिद्ध गौंधीवादी क्यों वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर दास जी बंग के नेतृत्व ए मुनि जी के मार्ग दर्शन तथा हम सबकी सक्रियता से आगामी 20 21 22 सितम्बर को सेवा ग्राम आश्रम सेवा ग्राम जिला वर्धा महाराष्ट्र से ऐसे किसी आन्दोलन की शुरुआत संभावित है।

हमारी स्पष्ट सोच है कि समाज सर्वोच्च हो। राजनीति धर्म नीति तथा अर्थ नीति पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करें तथा कोई किसी के कार्य में दखल न दें। ये तीनों समाज के प्रति उत्तर दायी हों। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति ने धर्म अर्थ को काबू में करके समाज पर हमला किया है इस लिए हमारा सीधा संघर्ष राजनीति से समाज को मुक्त कराने से शुरू होगा। हम किसी भी रूप में धर्म या अर्थ नीति के साथ संघर्ष नहीं करेंगे भले ही राजनीति हमें उस ओर ले जाने का प्रयत्न ही क्यों न करें। यदि एक बार राजनीति पर आशिक नियंत्रण में सफलता मिल जाती है तो आर्थिक या धर्मिक नीतियाँ तो अपने आप स्वतंत्र हो सकती है।

हम आप सब साथी कई वर्षों से आन्दोलन की प्रतीक्षा करते रहे हैं। सौभाग्य से हमें प्रसिद्ध गौंधीवादी ठाकुर दास जी बंग का नेतृत्व भी मिल रहा है तथा ससामाजिक राजनीति के दुर्लभ चिन्तक बजरंग मुनि जी का मार्गदर्शन भी। अब हम सब को सक्रिय होना है। सितम्बर 20 21 22 तीन दिनों के लिये आप अधिक से अधिक मानसिक तैयारी के साथ सेवाग्राम आइये। सेवाग्राम में आन्दोलन की योजना बनेगी। निवेदक

आचार्य पंकज